स्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। यदि उन्हें कोई [illegible]यता नहीं दी गई, तो वह दिन दूर नहीं, ज[illegible]ा उद्योग समाप्त हो जाएगा।

'IMA'

अतः अनुरोध है कि कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई जा रही पी०वी०सी० फिल्मों पर लगाया गया 31½ प्रतिशत उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया जाए और कैलेंडरिंग कारखानों द्वारा खरीदे गए मौलिक कच्चे माल पर वसूल किया गया शुल्क वापस किया जाए।

(ii) Need to effect basic changes in the field of research

श्री मूल चन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक जगत में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। विज्ञान के चरण बहुत तेज और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए भारत सरकार ने करीब 150 प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं, जहां बड़े और छोटे वैज्ञानिकों द्वारा शोधकार्य होता है। केन्द्रीय सरकार हर साल 570 करोड़ रुपया इन शोध प्रयोगशालाओं पर खर्च करती है। यह बात निर्विवाद सही है कि इन शोधशालाओं से आय लगभग शून्य है, जबकि खर्च उसकी तुलना में बढ़ा-चढ़ा है। क्या आज तक कभी इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि ये शोधशालाएं समाज की कौन-कौन सी जरूरतों को मद्देनजर रख कर काम कर रही हैं और इनकी उपलब्धियां पिछले पांच वर्षों में जो हुई हैं, क्या वे सन्तोषजनक हैं? आज वैज्ञानिक जगत में बढ़े हुए देश अमरीका, रूस, यूरोप में वैज्ञानिकों और उद्योगों के बीच में गहरा जिन्दा लेन देन दिखाई पड़ता है। समस्या और समाधान के बीच जो सुन्दर और सलोने पुल बंधे हुए हैं, भारत में उन का सर्वथा अभाव है। इन शोधशालाओं में वैज्ञानिकों की ज्यादा ताकत शोध करने में नहीं, फार्म भरने में और प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करने में लगाई जाती है। आज कई वैज्ञानिक शोधशालाओं में शानदार उपलब्धि के बजाय शानदार प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार के माहौल ने अच्छे वैज्ञानिकों को विदेश जाने के लिए मजबूर किया है और जो बाहर हैं, वे भारत लौटने को आतुर नहीं हैं। अतः सरकार को शोध के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन और परिवर्धन करना होगा ताकि जो धनराशि खर्च होती है, उससे समाज और देश को लाभ मिल सके और वैज्ञानिक जगत में भारत प्रगतिशील देशों की दौड़ में पीछे न रहे।

(iii) Need for setting up proposed Railway Coach Factory in Palghat, Kerala

*SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Sir, Kerala is an industrially backward State. For the past many years a demand has been raised for setting up a railway coach factory in that State. The Government of Kerala had promised to provide all infrastructural facilities at concessional rates. As a matter of fact, there is no major railway installation in Kerala.

Now, there is a report that an expert team has been sent to Kerala to make preliminary study for setting up a coach factory in Kerala. It is indeed a very heartening step. I hope that the Government will take an expeditious decision on the report of this team. In this context I may mention that Palghat is the most suitable place for setting up this factory. All the required facilities are available there. Therefore, I earnestly request the Government to take speedy steps to set up this coach factory at Palghat itself.

(iv) Need to take steps to increase the rice production in the country

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): In spite of the commendable achievements made in our agriculture, especially on the rice front, breaking the stagnation level of 53 to 54 million tonnes and reporting a score of 57 million tonnes in the year 1983-84, India's achievement in per hectare yield in rice is actually poorer than many countries, including some developing ones.

The experience with high-yielding varieties has shown that when the ecology of the rice

*Original speech was delivered in Malayalam.